**श्री रवि शंकर प्रसाद**: सभापति जी, माननीय सदस्या इस बात को समझेंगी कि सरकार खबरों पर निंयत्रण नहीं रखती, नियंत्रण रखने का काम सम्पादकीय मंडल का हैं । इसलिए हमने इस बात कि विशेष चिंता की हैं कि सम्पादकीय मंडल में भारतीय लोग हों । यह हमारी गाइड-लाईस में हैं । सरोज जी, आज तो एक बटन पर, इंटरनेट पर पूरी दुनिया का समाचार हमारे सामने होता हैं । आज दुनिया बदल रही हैं ।

**श्रीमती सरोज दुबे**: आम आदमी के पास इंटरनेट कहां हैं ?

**श्री रवि शंकर प्रसाद** : दुनिया बदल रही हैं । तो बदलती हुई दुनिया के अनुसार हम लोगों ने व्यापक विमर्श करके यह निर्णय लिया हैं और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय हित हमारी राजनीतिक, सामाजिक चिंताओं का इसमें पूरा ध्यान रखा गया हैं और आपकी जो आशंकाएं हैं वे आशंकाएं निर्मूल हैं , यह मैं कहना चाहता हूं ।

## Inland Water Transport System

*82. MISS MABEL REBELLO.†
SHRISANTOSH BAGRODIA:

Will the Minister of SHIPPING be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal of introducing inland water transport system in all cities that have some river running through it;

(b) whether Government plans to offer inland water transport as an economical transport service to the people; and

(c) if so, by when such transportation system is likely to be introduced in all cities that have rivers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI DILIP KUMAR MANSUKHLAL GANDHI): (a) and (c) No, Sir. Do not arise.

(b) Yes, Sir. Government are committed to the development of inland water transport as an efficient, environment friendly and economical means of transport for cargo and passengers. With this end in view the Ganga from Haldia to Allahabad, the Brahmaputra from Dhubri to Sadiya and the West Coast canal from Kottapuram to Kollam along with Champakara and Udyogmandal canals have been declared as National Waterways.

† The question was actually asked on the floor of the House by Miss Mabel Rebello.

MISS MABEL REBELLO: Sir, Inland water transport is an efficient environment-friendly and economic means of transport for cargo and passengers. But ony an amount of Rs. 120 crores was spent in the Ninth Five Year Plan. I would like to know from the hon. Minister what is the amount earmarked in the Tenth Five Year Plan for inland water transport, which are the national transport ways that he is planning to take up and which are the rivers. I would like to have the details.

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी**: राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में 668 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं । अभी तक इन तीन महीनों के दौरान 65 करोड़ रुपये उस पर खर्च हुआ हैं और छह नये जल मार्ग सुधार की बात हमने की हैं । एक कलकत्ता से इलाहाबाद हैं । **...(व्यवधान)...**

**कुमारी मैबल रिबैलो :** चेयरमैन साहब, केबिनेट मिनिस्टर जवाब देने के लिए आते नहीं हैं ।

**श्री सभापति :** आयेंगे कभी न कभी ।

**कुमारी मैबल रिबैलो :** सर, हमारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए नहीं आयेंगे तो हमको क्या फायदा होगा?

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी**: सभापति महोदय, एक सुदरवंन हैं, काकीनाड़ा हैं , ब्राह्मणी नदी हैं , डीवीसी नहर हैं, बारक नदी हैं और राष्ट्रीय जल मार्ग नम्बर तीन हैं । ऐसे छह नये मार्गो का हम निर्माण कर रहे हैं ।,

MISS MABEL REBELLO: Mr. Chairman, Sir, recently, the Ministry of Shipping has announced ninety per cent grant for the States Inland Waterways Development and hundred per cent for North-Eastern States including Sikkim. Inspite of that, hardly anybody has taken interest. I would like to know the reasons of this apathy. Why is there no stimulus? Is it because they have got a PSU known as Central Inland Water Transport Corporation. This Central Inland Water Transport Corporation also has been neglected and this is supposed to be the nodal agency. Are they going to do something for this nodal agency so that the State Governments can taken advantage of this grant-in-aid and this task force, which is formed for interlinking these rivers? Are they planning to formulated any scheme to see that rivers are connected to take advantage of transport, passengers, as well as, cargo?

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी**: सभापति महोदय जो नदियों को जोड़ने की बात हैं वह तो जल संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आती हैं । दूसरा, इनलैंड वाटर के डेवलेपमैंट के लिए हमने एक नई स्कीम लांच की हैं । पहले पचास परसेंट केन्द्र सरकार का और पचास परसेंट राज्य सरकार का हिस्सा था। उसमें राज्य सरकार 50 प्रतिशत हिस्सा दे नहीं पाती थी, इसलिए जिस गति से डेवलपमेंट होना चाहिए, वह नहीं हो पाता था । इसीलिए हमने एक स्कीम लांच करके ...(**व्यवधान**)....

**कुमारी मैबल रिबैलो :** क्यों नहीं हो रहा हैं? I Would like to know that even after the announcement of ninety per cent grant, why has nobody taken advantage of it?

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी:** सभापति महोदय, अब केन्द्र सरकार 90 परसेंट सबसिडी के तौर पर दे रही हैं । पहले यह कर्ज के तौर पर दिया जाता था । अब इसमें 10 परसेंट भागीदारी राज्य सरकारों की रहेगी और उसके माध्यम से तेजी से इसका डेवलेपमेंट होगा ।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: What is this ADB? I understand this as some technical assistance along with financial assistance which they are giving. By what time do you think we can have the waterways where cargo and passengers can move according to the international standards?

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी :** सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने आपके माध्यम से जो सवाल पूछा हैं, उसके बारे में मेरा कहना यह हैं अभी तक तीन राष्ट्रीय जल मार्ग बने हैं और छह नये बनाने की बात चल रही हैं । इसमें हमने यह कोशिश की हैं कि 330 दिन तक शिप चलें और दो मीटर की गहराई का कांस्टेट मैनटेन हो । हमने इस प्रकार की कार्यवाही करके इसको जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश की हैं ।

**श्री लेखराज वचानी**: सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जाना चाहता हूं कि वर्षों से इनलैड वाटर ट्रासपोर्ट और रिवर वाटर ग्रिड की बातें चल रही हैं क्या दोनों डिपार्टमेंट के बीच में कोई कोआर्डिनेशन हुआ हैं अथवा कोई स्कीम तैयार हुई हैं? इनलैड रिवर ट्रांसपोर्ट और इसके साथ-साथ जो रिवर वाटर ग्रिड हैं इन दोनों का किस तरीके से कोआर्डिनेशन हो सके जिससे कि देश को फायदा हो सके, इसके बारे में वर्षो से बात चल रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि यह कहां तक पहुंची हैं?

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी**: महोदय, यह जो अन्तर्गत पैसेंजर चलाने की बात हैं । यह राज्य सरकार के अन्तर्गत आती हैं । राज्य सरकार जिस प्रकार से सहयोग करेगी उसी पर वह निर्भर रहेगी कि किस प्रकार से इसको चलाया जाए ।

SHRI M.J. VARKEY MATTATHIL: Mr. Chairman, Sir, I understand that the coast canal from Kottapuram to Kollam along with Champakara and Udyogmandal canals have been declared as National Waterways. I

would like to know from the hon. Minster: how much money has been allotted to the State Government of Kerala for this project? At the same time, we do not require linking of rivers in Kerala, as water is always flowing around the coastal areas.

**श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी :** सभापति महोदय, यह पश्चिम तट केरल की ओर आता हैं उसके लिए 65 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया हैं।

**श्री सभापति :** मंत्री जी ने पहली बार जवाब दिए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। इसके लिए इनको इनकरेज करना चाहिए।

**Financial assistance to NGOs and various organisations**

83. SHRIDWIJENDRA NATH SHARMAH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) the details of financial assistance granted to various voluntary organizations and NGOs functoning at present in different parts of the country during the last three years, NGO-wise/State-wise;

(b) whether some proposals received from the State of Assam for providing grants to NGOs are pending with Government;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps being taken by Government to clear all the pending proposals for providing financial assistance to NGOs in the State of Assam?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) The Ministry of Social Justice and Empowerment has released grant-in-aid assistance to NGOs in the last three years and current financial year as under:

(Rs. in crores)

| SI. No. | Items | Year | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 (as on 20.02.03) |
| 1 | No. of NGOs | 2056 | 1961 | 2665 | 2375 |
| 2 | Amount released | 153.48 | 161.65 | 190.20 | 185.63 |

State-wise details are annexed as Statement-! (See below)